लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 330
दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

330. श्री के. सुधाकरनः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कन्नूर, केरल में हथकरघा उद्योग के समक्ष आने वाली गंभीर चुनौतियों से अवगत है जिनमें जीएसटी और आयकर का बोझ, धागे की बढ़ती लागत, पावरलूमों से प्रतिस्पर्धा, बुनकरों की घटती भागीदारी, अपर्याप्त विपणन और सहकारी समितियों में वित्तीय संकट शामिल हैं;

(ख) हथकरघा सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन पर जीएसटी दरों (5-35 प्रतिशत) और आयकर (30 प्रतिशत) की समीक्षा और उन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कन्नूर के बुनकरों के लिए धागे की बढ़ती लागत और आपूर्ति शृंखला की समस्याओं के समाधान के लिए कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत क्या उपाय लागू किए गए हैं; और

(घ) कन्नूर के हथकरघा उद्योग और इसकी निर्यात क्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) कन्नूर में कौशल विकास, डिजिटल मार्केटिंग पहल और सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए आवंटित केंद्रीय वित्त पोषण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय कन्नूर, केरल सहित देश भर में हथकरघा को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और (ii) कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) जैसी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण, सामाजिक सुरक्षा, विकट परिस्थितियों में पुरस्कार विजेता बुनकरों को भुगतान आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हस्तनिर्मित वस्त्र उत्पादों पर अधिकतर 5% की जीएसटी दर लागू होती है। जहां तक हथकरघा सहकारी समितियों पर आयकर का भार/आयकर में कटौती का सवाल है, इस मंत्रालय में ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, आरएमएसएस के तहत यार्न की लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को हल करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी), जोकि एक कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में कार्य कर रहा है, के माध्यम से मूल्य सब्सिडी और परिवहन सब्सिडी घटकों के तहत हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर रहा है।

(घ): आईआईएचटी, कन्नूर केरल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाला एक संस्थान है। हांलाकि, वस्त्र मंत्रालय समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बिना किसी राज्य-वार निधि आबंटन किए केरल सहित पूरे भारत में कौशल विकास कार्यक्रम सुविधा उपलब्ध कराना है। समर्थ योजना के अंतर्गत, 17.07.2025 तक, कन्नूर जिले सहित केरल राज्य में कुल 1,724 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है।

हथकरघा उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग के लिए, 22 अप्रैल 2023 को एक ई-कॉमर्स पोर्टल (Indiahandmade.com) लॉन्च किया गया ताकि पूरे भारत में बुनकरों और कारीगरों को बिना किसी बिचौलियों को शामिल किए अपने उत्पाद बेचने की सुविधा मिल सके।

******